श्री राजीव प्रताप रूडी : यह शब्द क्यों आया, इसका जवाब नहीं दिया।

MR. CHAIRMAN: Mr. Rudy, please.

प्रो. राम गोपाल यादव : सभापति जी, पूरे देश को इस बात की चिंता रही कि आखिर "बलूचिस्तान" शब्द आपकी कम्युनीक में आया कैसे? माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह specially जानना चाहता हूं कि यह बलूचिस्तान शब्द उस communique में कैसे आया, जब कि वहां से हमारा कभी कोई वास्ता नहीं रहा है और न ही हमारी तरफ से कभी कोई intervention रहा है, फिर भी हम स्वयं अपने आपको दोषी मान लें, यह कैसे हुआ?

SHRI S.M. KRISHNA: Sir, he has again repeated the same question. I am afraid, I have to repeat the same answer ...*(Interruptions)*... We have never. ...*(Interruptions)*... Balochistan, and it is a fact that Balochistan figured in that statement ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : कृपया आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... Don't interrupt.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Silence of the Prime Minister makes the whole thing a suspect ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, Mr. Rudy, you had your chance ...*(Interruptions)*... Panyji, your name has not been called. Please, resume your places ...*(Interruptions)*... There shall be no agitation in the House. Please, resume your places. ...*(Interruptions)*... कृपया आप लोग बैठ जाइए ....(**व्यवधान**)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं भी आग्रह करूंगा कि प्रधान मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए ...(**व्यवधान**)... यह बहुत गंभीर विषय है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, resume your places. Allow the Question Hour to proceed. Mr. Rajeev Shukla.

SHRI RAJEEV SHUKLA: It is obvious now that in order to cover up their own mistakes, as far as promoting terrorism in India is concerned, Pakistan always brings Balochistan to the forefront. I want to know from the hon. Minister that Pakistani leaders have been saying from long that they have given credible evidence to India for its role in Balochistan. Have you received any evidence till now from Pakistan?

SHRI S.M. KRISHNA: Not even a shade of it; nothing has been heard from Pakistan.

'सैनिक फार्म्स' में मकानों को नियमित किया जाना

†*204. **डा. प्रभा ठाकुर** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के 'सैनिक फार्म्स' क्षेत्र में बने हुए मकानों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की इस क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों निवासियों से विकास शुल्क लेकर उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए इन मकानों को नियमित किए जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

†Original notice of the question was received in Hindi

विवरण

(क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि डाटाबेस बनाने के दिल्ली नगर निगम के प्रयासों के भाग के रूप में उनके द्वारा 2008 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार सैनिक फार्म्स क्षेत्र में 1650 पते/मकान पाए गए जिनमें से अधिकांश रिहायशी स्वरूप के हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश 2007 जारी किए हैं और दिशानिर्देश सैनिक फार्म सहित संपन्न वर्गों द्वारा बसाई गई अनधिकृत कालोनियों से संबंधित नहीं है।

Regularisation of houses in Sainik Farms

†204. DR. PRABHA THAKUR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of existing houses in Sainik Farms area of Delhi;

(b) whether Government has formulated any plan to regularise these houses in order to provide basic facilities to the hundreds of residents living in that area after charging development fee from them; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI SAUGATA RAY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The Municipal Corporation of Delhi (MCD) has informed that as per survey got conducted by it in 2008 as part of MCD's efforts to create database, 1650 addresses/buildings were found in the Sainik Farms area, most of which are residential in nature.

(b) No, Sir.

(c) The Government has issued Revised Guidelines 2007 for regularization of unauthorized colonies in Delhi and the Guidelines do not relate to unauthorized colonies inhabited by affluent sections including Sainik Farms.

डा. प्रभा ठाकुर : महोदय, मैंने दिल्ली के "सैनिक फार्म्स" कॉलोनी के नियमन के बारे में प्रश्न पूछा था। उसके जवाब में जो आया है, उसमें लिखा है कि सैनिक फार्म्स में 2008 के सर्वे के अनुसार 1650 पते/मकान पाए गए हैं और वे रिहायशी हैं। मैंने पूछा था कि क्या उसमें उनको कोई मूलभूत सुविधाएं देने के लिए इस कॉलोनी को regularise करने की सरकार का कोई विचार है, तो उसका जवाब नहीं में आया है। इसके लिए कारण बताया गया है कि 2007 में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुसार "सैनिक फार्म्स" को संपन्न वर्गों द्वारा बसाई गई अनधिकृत कॉलोनी माना गया है, इसलिए यह regularise नहीं की जाएगी। महोदय, मैं शहरी विकास मंत्री, श्री एस. जयपाल रेड्डी जी को बहुत appreciate करती हूं। उन्होंने दो हजार से ज्यादा कच्ची बस्तियों का नियमन किया है।

†Original notice of the question was received in Hindi

महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या "सैनिक फार्म्स" में केवल संपन्न लोग ही रहते हैं, सारे rich लोग ही रहते हैं? जो 1650 मकान या और भी जो मकान हैं, क्या उनमें कोई आम आदमी, मध्यम श्रेणी के मिडिल क्लास के लोग रहते हैं? अगर रहते हैं, तो उनकी कितनी तादाद है? इसके अलावा इतने जो मकान बन गए हैं, ये मकान क्यों बने, कैसे बने और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, उन पर कोई कार्रवाई हुई? सभी जानते हैं कि ...

श्री सभापति : आप एक सवाल पूछिए।

डा. प्रभा ठाकुर : ठीक है, एक सवाल का जवाब आ जाए, तो फिर दूसरा supplementary पूछूंगी।

SHRI SAUGATA RAY: Sir, the MCD has informed us that as part of the first phase of efforts to create a data base, a private agency has carried out a survey in the Sainik Farms area. The survey revealed a total of 1650 addresses/buildings in the Sainik Farms area, which are largely residential in nature. The second phase of the effort is to commence soon whereby three-dimensional data base would be generated on the addresses/buildings in the colony. The thing is that while doing the survey, the MCD did not have access to the houses. They had high walls and large gates which were very well barricaded. So, we are trying to get it from the three-dimensional data, if it is possible. But, as far as we know, 'aam admi' do not live in the Sainik Farms.

डा. प्रभा ठाकुर : सर, यह मामला तो बहुत गंभीर है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आम आदमी वहां रहते ही नहीं हैं, तो पहले तो यह सर्वे कराया जाए कि कितने आम आदमी वहां रहते हैं? मैं मंत्री महोदय के जवाब से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वहां समृद्ध भी रहते हैं, वी.आई.पी. भी रहते हैं और आम आदमी भी रहते हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जिनकी मिलीभगत से ये मकान बनते हैं, जिन अधिकारियों की "मैं हूं ना" की प्रेरणा से ये बनते हैं, "मैं हूं ना" के अंदाज में वे कहते हैं कि आइए, मकान बनाइए, मैं आपके interest को protect करूंगा, तो उनमें से कितने suspend किए गए और उसके बाद वापस कितने बहाल कर दिए गए? क्या आप उन मकानों को तोड़ने की कार्यवाही करेंगे या फिर वे मकान बने रहेंगे? और यदि बने रहेंगे, तो फिर उनको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए, यह बताइए।

MR. CHAIRMAN: Please reply to one question.

SHRI SAUGATA RAY: Basically, Sir, the unauthorised affluent colony, called the Sainik Farms, has a long history. It was started in the late sixties as a cooperative society for rehabilitation of war widows and retired Defence personnel.

With Government support, land was purchased by the society and allotted to the Defence personnel for farmhouses. Over time, the area, commonly known as Sainik Farms, has attracted many non-Defence persons also. There are many plots with large houses and villas including swimming pools and duck pools in the colony.

The situation of this colony has been further complicated by the issuance of notices for acquisition of land. Some affected parties challenged the acquisition proceedings, and, in many cases, as a result of the orders of the court, acquisition proceedings have been quashed.

Some cases are still reported to be pending. But no demolition can take place because there is the NCT of Delhi Laws (Special Provisions) Act, which is valid up to 31.12.2009 and the proposal is there to extend the same up to 31.12.2010, which is under consideration of the Government. Till this law is in operation, no demolitions can take place there.

SHRI MOTILAL VORA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister as to whether any permission was taken for construction of these 1,650 houses in the Sainik Farms. This is first part. Secondly, out of 1,650 houses, how many houses are lying vacant? Sir, last part of my question is about the unauthorised colonies, which are going to be regularized as per the notification. By what time, these unauthorized colonies are to-be regularised?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, there is no question of taking any permission for building any of these houses. This is entirely... *...(Interruptions)...*

SHRI MOTILAL VORA: Without permission, how can they construct houses in Sainik Farms? *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : सुन लीजिए।

SHRI SAUGATA RAY: Sir, this is entirely an unauthorised colony built in violation of building norms and all sorts of regulations. It is not possible for the Ministry to find out as to how many houses are occupied and how many are not occupied because the MCD officials are not allowed ingress to the houses, and, do the survey from outside, *...(Interruptions)...*

SHRI MOTILAL VORA: Sir, the answer is not satisfactory. *...(Interruptions)...* Sir, I would like to know... *...(Interruptions)...* Sir, I need your protection. *...(Interruptions)...* Sir, I need your protection. *...(Interruptions)...* Sir, can anybody construct houses in the Sainik Farms?

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आप क्या बोल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* Next. *...(Interruptions)...* Dr. Heptulla, please.

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान उसकी ओर खींचना चाहूंगी कि इन्होंने House में admit किया है कि Sainik Farms unauthorised है। अगर यमुना पुश्ता पर गरीब लोग रहते हैं, तो उन unauthorised colonies को तोड़कर आप उन लोगों को सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन यहां जो लोग रह रहे हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। ये अपनी बिजली बनाते हैं, धरती में से अपने आप पानी खींचते हैं, म्युनिसिपल टैक्स नहीं देते, खुद अपनी सीवेज लाइन डालते हैं, तो क्या भारत सरकार इस तरह के independent Sainik Farms को बनाने की इजाज़त देती है? क्या उनका नाम Republic of Sainik Farms कहलाएगा?

SHRI SAUGATA RAY: Madam, you would be happy to know that in the year 2007, Cabinet took a decision to regularise all unauthorised colonies. The process *...(Interruptions)...* Please *...(Interruptions)...* The process was started and 1639 applications were received by the Government. Out of that, the Government of National Capital Territory of Delhi has issued provisional regularisation certificates to 1280 unauthorised colonies. Sainik Farms was kept out of the ambit of this. *...(Interruptions)...*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: You have not done your homework. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAUGATA RAY: I have done my homework. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I know that ...*(Interruptions)*... You are making a wrong statement. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAUGATA RAY: Sir, as the hon. Member asked, the Sainik Farms people are charged property tax by the Municipal Corporation of Delhi. They are supplied electricity by Delhi Electric Supply Undertaking. But they are not given any water; nor are there any arrangement for sewerage, drainage or solid waste management. ...*(Interruptions)*... because they are unauthorised and these facilities are not extended there. ...*(Interruptions)*...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, I ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Will you please resume your place? ...*(Interruptions)*... Yes, Shri Prakash Javadekar.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, the question is same. You are saying that this is an unauthorised colony. It is not the question of one colony alone. The question of regularisation of unauthorised colonies in Deihi has been there for the last so many years, और उसमें भी conflicting reports हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन unauthorised colonies को बसने का प्रमाण पत्र आपने चुनाव के पहले दिया था क्या उन सभी colonies को अधिकृत किया गया है? वह हुआ है या दूसरी काई रिपोर्ट आयी है?

SHRI SAUGATA RAY: Sir, as I stated earlier, Cabinet took a decision on 08.02.07 to regularise unauthorised colonies, both existing ...*(Interruptions)*... Just a moment. ...*(Interruptions)*... both existing on public sand as well as on private land. However, it was decided that for affluent colonies like Sainik Farms, a separate policy will be evolved later on. ...*(Interruptions)*... Applications for regularisation of unauthorised colonies ...*(Interruptions)*...

ONE HON. MEMBER: What is the separate policy? ...*(Interruptions)*...

डा. वी. मैत्रेयन : उसके बाद दो साल हो गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : अभी आपने कहा कि regularise कर दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप सुन तो लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Different policies for different people are there. ..*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Rudy, please ...*(Interruptions)*...

SHRI SAUGATA RAY: Applications for ...*(Interruptions)*... Please listen to this. Applications for reguiarisation of unauthorised colonies were invited by the Government of National Capital Territory of Delhi and a total of 1639 applications were received. The GNCTD has also issued provisional regularisation certificates to 1280 unauthorised colonies, and you would be happy to know

that ...*(Interruptions)*... in these unauthorised colonies, the work of ...*(Interruptions)*... construction of roads, drainage, water supply has been taken up and during the financial year 2008-09, an amount of Rs. 885 crores has been sanctioned. ...*(Interruptions)*... During the financial year 2009-10, a provision of Rs. 786 crores has been made ...*(Interruptions)*... and Rs. 638 crores have been released. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर : बजट कहां से आया? ...(**व्यवधान**)...

SHRI SAUGATA RAY: The progress is being monitored by the GNCTD. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question Number 205. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: What is this, Sir? ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ: They are taking the House for granted. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I think, you have been heard across the House. Thank you. ...*(Interruptions)*... Question No. 205 please. ...*(Interruptions)*...

श्री कमाल अख्तर : महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप अभी नहीं पूछ सकते।

श्री कमाल अख्तर : सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सप्लीमेंटरी पूछने के लिए बड़ा नेता होना या आगे बैठना जरूरी है?

श्री सभापति : नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 205.

Assessment of urban poverty

*205. SHRI R.C. SINGH: Will the Minister of HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether as per the estimates of the Planning Commission, urban poor for the years 1993-94 and 2004-05, based on the Uniform Recall Period method, has increased from 76 million to 91 million during this period;

(b) whether any assessment has been made by her Ministry or any other agency to find out the condition of migrants who have reached urban areas from villages;

(c) the details thereof;

(d) whether the India Urban Poverty Report, 2009, finds gender discrimination affecting women greatly; and

(e) the details of schemes, with physical targets and achievements during the last three years targeting women among urban poor?